तिब्बत देश

दलाई लामा के फैसले से हताश चीन सरकार

तिब्बत में इतिहास इन दिनों एक नई करवट ले रहा है। पिछले 470 साल से चली आ रही धार्मिक शासन परंपरा को त्यागते हुए दलाई लामा के नेतृत्व वाली तिब्बती निर्वासन सरकार ने ठेठ लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने का फैसला किया है। धर्मशाला में 29 मई की रात देर तक चली बहस के बाद तिब्बती निर्वासन संसद ने आखिरकार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके तिब्बती संविधान में आमूल चूल परिवर्तन करने का ऐतिहासिक फैसला कर ही डाला।

अगली सुबह इस फैसले पर दलाई लामा ने अपने हस्ताक्षर करके सन् 1642 से चली आ रही गादेन–फोड्रांग शासन व्यवस्था को भंग कर दिया। दलाई लामा के नेतृत्व में चलने वाली इस धर्मशासक प्रणाली की जगह अब आम जनता के वोट से जीत कर आने वाले 'कालोन ट्रीपा' (प्रधानमंत्री) के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार तिब्बती जनता का नेतृत्व करेगी।

इससे पहले एक दलाई लामा के देहावसान के बाद अगला शासक उनका नया अवतारी बालक होता था। तिब्बती शासन परंपरा में दलाई लामा को वे सब अधिकार प्राप्त थे जो भारतीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री, अमेरिका में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में महारानी या महाराजा, वेटिकन में पोप और किसी तानाशाही व्यवस्था में वहां के शासक को प्राप्त होते हैं। 76 वर्षीय वर्तमान दलाई लामा (निजी नाम 'तेनज़िन ग्यात्सो') इस परंपरा में 14वें हैं।

इस ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन की एक बड़ी खासियत यह है कि ये सभी परिवर्तन स्वयं दलाई लामा के आग्रह और निर्देश पर किए गए हैं। हालांकि इस तरह के परिवर्तन लागू करने का एक प्रयास उन्होंने लगभग 20 साल पहले भी किया था, लेकिन तब जनप्रतिनिधियों ने भावुकता भरी दलीलें देकर उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया था। इस साल 14 मार्च को दलाई लामा ने एक बार फिर संसद से ऐसे संवैधानिक परिवर्तन करने का आग्रह किया जिससे वे अपने सभी राजनीतिक अधिकार और संवैधानिक शक्तियां निर्वाचित प्रधानमंत्री और संसद को सौंप सकें।

लेकिन तिब्बती संसद ने दो बार उनके इस प्रस्ताव को उनके 'पुनर्विचार' के लिए उन्हें वापस भेज दिया। संसद की इस जिद को देखते हुए दलाई लामा ने मजबूर होकर संसद को तिब्बती नेतृत्व की व्यापक 'आम सभा' बुलाने और इस प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया। लेकिन आम–सभा ने भी उन्हें कम से कम 'राष्ट्राध्यक्ष' पद स्वीकार करने का आग्रह किया। आखिरकार दलाई लामा ने संसद को निर्देश दिया कि वह 30 मई को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले संविधान में उपरोक्त परिवर्तन वाला प्रस्ताव पारित कर उनके अनुमोदन के लिए पेश करे।

पिछली लगभग 25 पीढ़ियों से दलाई लामा के सामने नतमस्तक होती आ रही आम तिब्बती जनता के लिए यकीनन यह परिवर्तन इतना बड़ा है कि इसे समझने और आत्मसात करने में उसे कुछ समय लगेगा। लेकिन बाकी दुनिया के लोगों के लिए भी दलाई लामा के निर्देश पर लाया गया यह बदलाव काफी अनापेक्षित है। किसी न किसी बहाने अपनी जनता के अधिकारों को छीनकर अपनी ताकत बढ़ाने वाले नेताओं को देखती आने वाली अंतर्राष्ट्रीय जनता के लिए भूटान के बाद दूसरा मौका है जब कोई नेता अपने अधिकार अपनी जनता को दे रहा है।

तिब्बत और दलाई लामा पर लंबे समय से नज़र रखने वाले विशेषज्ञ जानते हैं कि दलाई लामा का यह कदम तिब्बत में लोकतंत्र लाने के उस अभियान की परिणति है जो वह 1959 में निर्वासन में आने के बाद पचास साल से चलाते आए हैं। 1951 में जब तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा जमाया उस समय दलाई लामा केवल 16 साल के थे। उस समय तिब्बत के प्रति दुनिया की उदासीनता को देखकर दलाई लामा को समझ में आ गया था कि तिब्बत को यह कीमत अपनी धर्म पर आधारित शासन प्रणाली और बाकी दुनिया से कटकर रहने की परंपरा के कारण चुकानी पड़ी है। यह भी कि किसी देश की व्यवस्था को केवल एक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा पर आधारित रखने के कितने नुकसानदेह परिणाम हो सकते हैं। यही कारण था कि निर्वासन में आने के तुरंत बाद उन्होंने 1960 में तिब्बत के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित करने का काम शुरू किया।

तिब्बती निर्वासन सरकार की पहली संसद और मंत्रिमंडल के सदस्यों को उन्होंने खुद नामांकित किया। लेकिन बाद में उन्होंने सांसदों के सीधे चुनाव और सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रणाली शुरू की। 1991 में उन्होंने तिब्बत को एक नया संविधान दिया जिसमें संसद को यह अधिकार भी दिया गया कि उचित समझने पर वह दलाई लामा को शासक पद से हटा सके। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने 2001 में संविधान में परिवर्तन करके प्रधानमंत्री के लिए भी सीधे चुनाव की परंपरा शुरू कर दी और अपने अधिकारों को केवल एक संवैधानिक शासकीय अध्यक्ष तक सीमित कर दिया। तब से आम तिब्बती शरणार्थी गुप्त मतदान के आधार पर तीन बार अपना प्रधानमंत्री चुन चुके हैं। और अब उन्होंने दलाई लामा के सभी राजनीतिक और शासकीय अधिकार निर्वाचित प्रधानमंत्री, निर्वाचित संसद और मुख्य न्यायाधीश में बांट दिए हैं।उनका अगला कदम पुनर्जन्म के आधार पर दलाई लामा के चुनाव की सन् 1642 से चली आ रही व्यवस्था को समाप्त करके अपने जीवनकाल के दौरान ही योग्यता के आधार पर अगले दलाई लामा की नियुक्ति की प्रणाली शुरू करना है।

चौंकाने वाली बात यह है कि दलाई लामा के उपरोक्त दोनों कदमों का सबसे तीखा विरोध चीन की कम्युनिस्ट सरकार की ओर से हो रहा है। बीजिंग की सबसे बड़ी परेशानी पुनर्जन्म के आधार पर दलाई लामा के चुनाव की प्रणाली को समाप्त करने के सवाल पर है। चीन सरकार ने दलाई लामा को तिब्बत की 'संस्कृति' को याद रखने और 'धार्मिक कर्मकांडों' को 'उचित सम्मान' देने की सलाह देते हुए उन्हें धमकाया है कि तिब्बत की एक हजार साल पुरानी परंपरा को बदलने का दलाई लामा या किसी व्यक्ति को हक नहीं है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कानून के फैलो और 43 वर्षीय नए प्रधानमंत्री लोबसांग सेंग्ये के चुनाव पर उनके तिब्बती युवा कांग्रेस से रिश्तों का हवाला देते हुए चीनी प्रवक्ता की टिप्पणी थी कि ''वह तो एक आतंकवादी है''। दलाई लामा के फैसले के बाद तिब्बती निर्वासन सरकार को भी उसने एक ऐसी 'गैरकानूनी' संस्था बता डाला जिसका गठन उसकी राय में 'चीन को तोड़ने' के लिए किया गया था।

चीन की हताशा भरी ये टिप्पणियां यह दिखाती हैं कि भिक्षु राजनेता के इस एक कदम ने चीन सरकार की उन सारी योजनाओं की हवा निकाल दी है जो उन्होंने दलाई लामा के देहावसान के इंतजार में तैयार की हुई थीं। पिछले लगभग बीस साल से बीजिंग के शासक इस तैयारी में लगे हुए थे कब दलाई लामा गुजरें और वे अपनी मर्जी के एक तिब्बती बच्चे को दलाई लामा के 'नए अवतार' के रूप में तिब्बत की गद्दी पर बिठाकर तिब्बती समस्या का एक 'स्थायी' हल निकाल कर निश्चिंत हो जाएं।1993 और 1995 में कम्युनिस्ट अध्यक्षता वाली 'अवतार खोजी' कमेटियों से कर्मा पा और पंचेन लामा जैसे वरिष्ठ पदों पर अपनी मर्जी के बच्चों की नियुक्ति करके वे इस खेल की पूरी ड्रेस रिहर्सल दो बार कर चुके हैं।

लेकिन दलाई लामा ने अपने सारे राजनीति अधिकार निर्वासन सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपने का फैसला करके और अगले दलाई लामा के निर्वाचन की नई प्रणाली शुरू करने की बात कह कर चीन सरकार के इरादों पर पानी फेर दिया है। नई व्यवस्था में अब चीनी नेताओं के लिए तिब्बत पर एक शक्तिहीन पिठ्ठू दलाई लामा थोपने की गुजाइश खत्म हो गई है। बल्कि वर्तमान दलाई लामा की मृत्यु के बाद तिब्बत की समस्या के खत्म होने की उसकी उम्मीदों पर भी ग्रहण लग गया है। क्योंकि एक व्यक्ति के बजाए लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के हाथों अपने राजनीतिक अधिकार सौंप कर दलाई लामा ने तिब्बती संघर्ष को अनंत जीवनदान दे दिया है।

– विजय क्रान्ति

विरोध करने पर तिब्बती भिक्षुणी को पीटा गया, जेल में डाला गया

चीन की सरकारी मीडिया की खबरों से भी अब इस बात की पुष्टि हो रही है कि कीर्ति मठ में 'देशभक्ति शिक्षा' अभियान चलाया जा रहा है। एक खबर में कहा गया है, "स्थानीय सरकार द्वारा 22 अप्रैल को जारी सर्कुलर के मुताबिक कीर्ति मठ के सभी भिक्षु चीनी संविधान, आपराधिक कानून और धार्मिक मामलों के नियम–कानून की बुनियादी जानकारी ले रहे हैं।"

(रेडियो फ्री एशिया, 28 अप्रैल)

कांडजे तिब्बती क्षेत्र के चीनी अधिकारियों ने पिछले हफ्ते एक तिब्बती बौद्ध भिक्षुणी को पहले पीटा और फिर जेल में डाल दिया। यह भिक्षुणी तिब्बत को आज़ाद करने के आह्वान वाले पत्रक बांट रही थी। तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) के प्रवक्ता जामपेल मोनल ने कहा कि बदाक फुंसोक छोलिंग ननरी की भिक्षुणी 28 वर्षीय जाम्पा सो 16 अप्रैल को देर्गे काउंटी के एक बड़े पुल पर खड़ी हो गईं और उन्होंने तिब्बत की आज़ादी के नारे लगाते हुए पत्रक बांटने शुरू कर दिए। टीसीएचआरडी ने देर्गे काउंटी सीट में जाम्पा सो को पीटे जाने और जेल में बंद करने की खबर की पुष्टि की है। जब जाम्पा के परिजन देर्गे काउंटी पुलिस हिरासत केंद्र पहुंचे तो उन्हें उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। टीसीएचआरडी ने कहा, "उनके परिवार को यह बताया गया कि जाम्पा सो ने एक गंभीर अपराध किया है और उन्हें यह धमकी भी दी गई कि वे दुबारा हिरासत केंद्र आने की जुर्रत न करें। गौरतलब है कि बडाक ननरी में साल 2008 के तिब्बती जनक्रांति के बाद भिक्षुणियों द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है।

टीसीएचआरडी ने कहा, "अधिकारियों ने धमकी दी कि यदि ननरी को किसी भी राजनीतिक गतिविधि में लिप्त पाया गया तो सरकार उसे बंद कर देगी।" टीसीएचआरडी ने जाम्पा को तत्काल रिहा करने की मांग की है। संगठन ने कहा, "उन्होंने साधारण तरीके से सिर्फ अपना मत व्यक्त किया था और यह एक बुनियादी अधिकार है।"

जेल में बंद कीर्ति मठ के 300 भिक्षुओं को उनके परिवार और रिश्तेदारों ने रिहा करने की मांग की

(30 अप्रैल, टिबेट डॉट नेट)

उत्तर–पूर्वी तिब्बत के कीर्ति मठ के करीब 300 भिक्षुओं को जेल में डाल दिया गया है। इसके विरोध में उनके परिवार और रिश्तेदारों ने नाबा काउंटी के क्षेत्रीय प्रशासन के सामने शिकायत दर्ज की है। भारत में धर्मशाला स्थिति कीर्ति मठ के एक भिक्षु कानयाग सेरिंग ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने 21 अप्रैल की रात को मठ से 300 भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान पिटाई से दो बुजुर्ग भिक्षुओं की मौत हो गई। इन 300 भिक्षुओं को कहां रखा गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। कानयाग ने बताया कि भिक्षुओं को इस तरह के मनमाने तरीके से गिरफ्तार करने के विरोध में गोलोग के छिगड्रिल जिले के खांगसरमा गांव में रहने वाले भिक्षुओं के परिवार एवं रिश्तेदार के लोगों ने नाबा जाकर शिकायत दर्ज कराई है। इन भिक्षुओं को तत्काल रिहा करने की मांग की गई है। ये रिश्तेदार जब करीब 20 कारों में नाबा की ओर जा रहे थे तो 10 बड़े सैन्य वाहनों में सवार चीनी सुरक्षा बलों ने उन्हें नाबा के क्षेत्रीय सरकार के कार्यालय से करीब 5 किलोमीटर पहले ही उन्हें रोक दिया और उन्हें छिगड्रिल पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद भी कीर्ति मठ से भिक्षुओं को मनमाने तरीके से गिरफ्तार करने की घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। 28 अप्रैल को स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे चार और भिक्षुओं को हिरासत में लिया गया जिनमें थावा घोंगमा के रहने वाले 28 साल के लोबसांग कुनछोक भी शामिल हैं। इसी प्रकार आत्मदाह कर लेने वाले भिक्षु फुंसोग का शव मठ के भीतर ले जाने के आरोप में सेरिंग दामडुल नाम के एक और भिक्षु को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

कीर्ति मठ पर दमनात्मक कार्रवाई जारी, चीन ने हालात सामान्य होने का ढोंग किया

(तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान, 29 अप्रैल)

तिब्बत के नाबा काउंटी में स्थित कीर्ति मठ में 60 साल से ऊपर के दो भिक्षुओं की मौत के बाद चीनी सुरक्षा बलों की दमनात्मक कार्रवाई जारी है। ये दोनों भिक्षु सुरक्षा बलों द्वारा मठ से भिक्षुओं को पकड़ कर ले जाने का विरोध कर रहे थे। चीन की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह स्वीकार किया कि एक तिब्बती महिला की मौत हो गई है, लेकिन यह मानना की उसकी मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार है, 'काल्पनिक' बात है। इस आधिकारिक रिपोर्ट में खासकर तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के बयान का हवाला दिया गया। चीन का यह बयान उसके अधिकारियों के विरोधाभासी बयान देने के उस परंपरा का ही हिस्सा है जिसके द्वारा इस दमनात्मक कार्रवाई और इलाके की स्थिति के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पिछले हफ्ते विदेशी पर्यटकों को वहां जाने से रोक दिया गया है और अब सरकार वहां की स्थिति को 'सामान्य' बता रही है।

वायस ऑफ अमेरिका की तिब्बती सेवा, बीबीसी

और अन्य कई टीवी चैनलों द्वारा पिछले हफ्ते दिखाए गए एक वीडियो फुटेज में यह साफ दिखता है कि 16 मार्च को कीर्ति मठ के 20 साल के भिक्षु फुंसोग के आत्मदाह कर लेने के बाद वहां सुरक्षा बलों का जमावड़ा हुआ है, तिब्बतियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। निर्वासित तिब्बती मठ के भिक्षुओं के अनुसार अब मठ के भीतर एवं बाहर निगरानी कैमरे लगा दिए गए हैं और भिक्षु अब भी अंदर बंद हैं। इस इलाके में लगातार आतंक का माहौल बना हुआ है क्योंकि लोगों के अचानक गायब होने की घटनाएं जारी हैं। उस इलाके के कई सूत्रों ने बताया कि चीनी अधिकारियों के रिपोर्ट के विपरीत तथ्य यह है कि 21 अप्रैल को मठ से सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा भिक्षुओं को पकड़ कर ले जाने का विरोध करने वाले दो लोग मार डाले गए हैं। ये दो लोग थे, 60 साल के दोंगको और 65 साल की महिला शेरकी। इनकी मौत सुरक्षा बलों द्वारा भारी पिटाई की वजह से हुई है। इन मौतों की पुष्टि करते हुए निर्वासित कीर्ति मठ ने कहा है कि चीनी अधिकारियों ने दोंगको के शव को भिक्षुओं के आशीर्वाद प्रार्थना के लिए मठ के अंदर नहीं ले जाने दिया, जबकि इस इलाके में किसी की मौत हो जाने पर ऐसा करने का रिवाज है और यह कई पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। इसी प्रकार कीर्ति मठ को 65 साल की शेरकी के लिए भी किसी तरह के परंपरागत प्रार्थना करने की इजाजत नहीं दी गई। निर्वासित कीर्ति मठ ने कहा, "भिक्षुओं को प्रार्थना के चार शब्द न कहने देना मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के लिए और भी व्यथा की बात है। चीन की सरकारी मीडिया की खबरों से भी अब इस बात की पुष्टि हो रही है कि कीर्ति मठ में 'देशभक्ति शिक्षा' अभियान चलाया जा रहा है। एक खबर में कहा गया है, "स्थानीय सरकार द्वारा 22 अप्रैल को जारी सर्कुलर के मुताबिक कीर्ति मठ के सभी भिक्षु चीनी संविधान, आपराधिक कानून और धार्मिक मामलों के नियम–कानून की बुनियादी जानकारी ले रहे हैं।"

इलाके में इस बात की भी अफवाह है कि यहां उच्च स्तरीय अधिकारियों का दौरा होने वाला है क्योंकि पुलिस दमनात्मक कार्रवाई के साक्ष्य मिटा रही है, सेना के रहने के अस्थायी इंतजाम जैसे टेंट आदि को हटाया जा रहा है। हालांकि यहां से सुरक्षा बलों को नहीं हटाया गया है।

तिब्बत के आमदो प्रांत में स्थित नाबा संकट के शुरू होने के समय से ही अधिकारियों ने जानबूझकर एक भय का वातारण बनाने का प्रयास किया और इस इलाके से किसी भी तरह की सूचना को बाहरी दुनिया तक पहुंचने से रोका। इसी प्रकार मीडिया को अंग्रेजी में लगातार ऐसे आधिकारिक बयान दिए गए जिसमें अंतरराष्ट्रीय मत और यहां के अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज को गलत ठहराने का प्रयास किया गया। अक्सर इस तरह की बयानबाजी में कई तरह के विरोधाभास होते थे। उदाहरण के लिए एक सरकारी बयान में कहा गया कि 'केवल कुछ ही भिक्षु सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हैं', लेकिन इसके बाद जारी एक बयान में कहा गया कि 'यह समस्या सिर्फ कुछ भिक्षुओं से नहीं जुड़ी है।' हालांकि, अधिकारियों का दावा है कि यह समस्या सिर्फ कीर्ति मठ तक सीमित है, लेकिन 21 मठ से ही पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इस इलाके में पहले से रह रहे विदेशियों को बाहर जाने का आदेश दिया गया। इस इलाके में विदेशियों की यात्रा पर प्रतिबंध के लिए प्रांतीय सुरक्षा ब्यूरो अधिकारियों के एक नोटिस में जारी किया और कहा गया कि यह तिब्बत के सिचुआन, कार्डजे इलाकों और नाबा प्रशासनिक क्षेत्र में लागू होता है। इस प्रतिबंध के लिए कोई वजह नहीं बताई गई।

उन्होंने कहा कि बहुत से तिब्बतियों की मौत 'एक तरह की राजनीतिक सुनामी' की वजह से हो रही है।

तिब्बत में कीर्ति मठ के छह अन्य भिक्षु गिरफ्तार

(फायूल, 30 अप्रैल)

गत 21 अप्रैल को चीनी सुरक्षा बलों द्वारा 300 भिक्षुओं की गिरफ्तारी के बाद अब यह सूचना मिल रही है कि नाबा तिब्बती क्षेत्र के अधिकारियों ने छह और भिक्षुओं को गिरफ्तार किया है। धर्मशाला स्थित कीर्ति मठ के एक भिक्षु कानयाग सेरिंग ने बताया कि गत 28 अप्रैल को नाबा कीर्ति मठ के 28 वर्षीय भिक्षु लोबसांग कुंछोक और इसी मठ के चार अन्य भिक्षुओं को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन भिक्षुओं को कहां रखा गया है। कीर्ति मठ के एक अन्य भिक्षु सेरिंग दामदुल को भी इसके कई दिनों पहले गिरफ्तार किया गया है। सेरिंग पर आरोप लगाया गया है कि वे 16 मार्च को आत्मदाह कर लेने वाले युवा भिक्षु फुंसोग का शव मठ के अंदर लेकर आने वाले लोगों में शामिल थे। गौरतलब है कि कीर्ति मठ के भिक्षु चीन सरकार के 'पुनर्शिक्षा' अभियान का कड़ाई से विरोध करते रहे हैं। यह मठ इस इलाके के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र में से है। हाल के वर्षों में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि राजनीति प्रेरित शिक्षा अभियान चलाने और मठों में धर्म पालन पर उत्पीड़न बढ़ते जाने से कई भिक्षु आत्महत्या जैसे चरम कदम उठाने लगे हैं।

न्होंने कहा कि एमनेस्टी को यह उम्मीद है कि मानवाधिकार मसला सिर्फ वार्षिक चर्चाओं में ही शामिल नहीं रहेगा बल्कि इसे व्यापक संपर्क प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा।

यूरोपीय संसद ने नेपाल से कहा, तिब्बतियों को मतदान करने दें

कई लोगों का कहना है कि चीन ने इसी वजह से पंचेन लामा को गायब कर एक दूसरे बालक ग्यालत्सेन नोर्बू को खुद ही पंचेन लामा घोषित कर दिया। चीन इस तरह से दलाई लामा के पुनर्जन्म में भी अपना हाथ रखने की कोशिश कर रहा है।

(आईएएनएस, 9 अप्रैल)

नेपाल द्वारा तिब्बती शरणार्थियों को अपनी नई निर्वासित सरकार चुनने के लिए वोट डालने से रोकने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए यूरोपीय संसद ने नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार से कहा है कि वह तिब्बतियों को वोट डालने दे। यूरोपीय संसद ने इसे एक बुनियादी अधिकार बताया है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और जिसकी गारंटी होनी चाहिए।

यूरोपीय संसद ने 5 अप्रैल के अपने प्रस्ताव में कहा है कि दुनिया भर में 82,000 से ज्यादा निर्वासित तिब्बती अपना नया प्रधानमंत्री और निर्वासित तिब्बती सरकार चुनने के लिए मार्च, 2011 में मतदान करने के लिए जुटे थे। लेकिन नेपाल सरकार ने चीन के बढ़ते दबाव की वजह से हजारों तिब्बतियों को इस कवायद का हिस्सा बनने से रोक दिया। यूरोपीय संसद ने कहा कि कहा कि तिब्बत की विशिष्ट आंतरिक चुनाव प्रक्रिया साल 1960 से ही चल रही है और यह तिब्बत के भीतर और बाहर विशिष्ट तिब्बती पहचान के संरक्षण और उसे मजबूत करने के लिए जरूरी है। यूरोपीय संसद के काठमांडू स्थित प्रतिनिध से कहा गया है कि वे नेपाल सरकार द्वारा तिब्बतियों के चुनाव पर रोक लगाने की कार्रवाई पर नेपाली और चीनी अधिकारियों से मिलकर कोई रास्ता निकालें। नेपाल सरकार ने तिब्बती समुदाय को प्रार्थना सभाएं आयोजित करने एवं अपने नेता दलाई लामा के जन्म दिन समारोह मनाने से भी रोक दिया है, इसलिए यूरोपीय संसद ने यह भी अनुरोध किया है कि नेपाल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते द्वारा नेपाल में हर नागरिक के साथ शरणार्थियों को भी मिले अभिव्यक्ति, सभा करने और संघ बनाने के अधिकार का आदर करे। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते में नेपाल भी शामिल है। यूरोपीय संसद ने यह भी मांग की है कि तिब्बती समुदाय के शांतिपूर्ण प्रदर्शन या सभा से पहले गिरफ्तारी और प्रतिबंध को खत्म किया जाए। यूरोपीय संसद ने कहा है कि इस तरह के अधिकारों और धार्मिक आज़ादी को नेपाल के नए संविधान में शामिल किया जाना चाहिए जो 28 मई, 2011 से प्रचलित होना है। नेपाल पर राजनयिक दबाव बढ़ाते हुए यूरोपीय संसद ने कहा कि नेपाल सरकार को नेपाल को चीन के इस दबाव का विरोध करना चाहिए कि नेपाल में तिब्बती समुदाय को 'शांत किया जाए'। तिब्बती समुदाय को शांत करने के लिए नेपाल ऐसे प्रतिबंधों का इस्तेमाल कर रहा है 'जो न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक गैर कानूनी भी है।

यूरोपीय संसद ने काठमांडू स्थित अपने प्रतिनिधि के माध्यम से यूरोप की विदेश कार्रवाई सेवा से कहा है कि वह नेपाल में राजनीतिक स्थितियों पर गहरी नजर रखें, खासकर तिब्बती शरणार्थियों के प्रति व्यवहार और उनके संवैधानिक एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक मिले अधिकारों पर।

यूरोपीय संसद ने कहा कि नेपाल पुलिस के लगातार तिब्बतियों के बुनियादी मानवाधिकार के उल्लंघन की खबरें हैं और तिब्बत में बहुत से शरणार्थियों खासकर तिब्बतियों की कुल मिलाकर स्थिति काफी चिंताजनक है।

पंचेन लामा के गायब होने पर अमेरिकी संगठन ने जताई चिंता

(सिफी डॉट कॉम, 11 अप्रैल)

जबरन या स्वैच्छिक रूप से लोगों के लापता होने पर गठित अमेरिकी कार्यसमूह ने कहा है कि वह लंबे समय से चल रहे लापता होने के कई मामलों पर चिंतित है जिनमें 1995 में गायब होने वाले 6 वर्षीय बालक गेधुन छोक्यी निमा का भी एक मामला शामिल है जिसे तिब्बत के 11वें पंचेन लामा के नाम से भी जानते हैं। समूह ने कहा, "चीनी अधिकारियों ने यह तो स्वीकार किया है कि बालक को वे ले गए हैं, लेकिन वे लगातार इस बात की जानकारी देने से इनकार करते रहे हैं कि उस बालक को कहां रखा गया है और वह कैसा है। इसलिए इसे जबरन लापता करने का ही मामला माना जा सकता है।" संगठन का कहना है कि जबरन लापता करने को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक अपराध माना जाता है।

अमेरिका ने कहा, चीन मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है

(वायस ऑफ अमेरिका, 28 अप्रैल)

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि चीन में नए मानवाधिकार समस्याओं पर अमेरिका चिंतित है। बीजिंग में चीनी अधिकारियों के साथ दो दिन तक मानवाधिकारों पर बातचीत के बाद उनकी यह टिप्पणी सामने आई है। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री माइकल पोसनर ने कहा यह बातचीत काफी विस्तार और गहराई से हुई और उनके प्रतिनिधिमंडल ने बढ़ती अमेरिकी चिंताओं से चीन

को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल को हुई इस बातचीत में इंटरनेट की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, तिब्बत और सीक्यांग जैसे मसले शामिल थे। पोसनर ने कहा, "हाल के महीनों में हमने मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन देखा है और पिछले दो दिनों में हुई मानवाधिकारों पर बातचीत में इन नकारात्मक रुख पर चर्चा हावी रही। हम हाल के महीनों में आई इन खबरों से काफी चिंतित हैं कि जनहित याचिका के वकीलों, लेखकों, कलाकारों सहित दर्जनों लोगों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के गिरफ्तार किया गया है, जेल में डाला गया है और कुछ लोगों को तो गायब ही कर दिया गया है।" पोसनर ने कहा, अमेरिका खासकर उन वकीलों की स्थिति को लेकर चिंतित है जो पुलिस हिरासत से गायब हो गए हैं। पोसनर ने कहा, "मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले में हमें निश्चित रूप से ऐसे सवाल नहीं मिले हैं जो हमें संतुष्ट कर सकें। कई मामलों में सही जवाब नहीं मिले हैं या जवाब ही नहीं मिले हैं।"

एमनेस्टी इंटरनेशनल एशिया–प्रशांत के निदेशक सैम जारिफी ने कहा कि इस बातचीत से पता चलता है कि अमेरिका और अन्य सरकारों को चीन के साथ लगातार मानवाधिकारों पर दबाव बनाते रहना होगा। जारिफी ने कहा, "मुझे लगता है कि इस समय महत्वपूर्ण बात यह समझना होगा कि इन वार्ताओं को वास्तव में प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए और यह बातचीत सिर्फ मानवाधिकारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि एमनेस्टी को यह उम्मीद है कि मानवाधिकार मसला सिर्फ वार्षिक चर्चाओं में ही शामिल नहीं रहेगा बल्कि इसे व्यापक संपर्क प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा।

तिब्बत के लापता पंचेन लामा के जन्म दिन पर जनजागरण और विरोध प्रदर्शन

(फायूल, 25 अप्रैल)

तिब्बती और उनके समर्थक लोगों ने दुनिया भर में 25 अप्रैल को 11वें पंचेन लामा गेंधुन छोक्यी निमा का 22वां जन्म दिन मनाया। पंचेन लामा को चीन सरकार ने लापता कर दिया है। पंचेन लामा के जन्म दिन पर जनजागरण रैली और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। चीन की कैद से पंचेन लामा को तत्काल रिहा कराने के लिए बढ़ते आंदोलन को और मजबूती देने के लिए ऑनलाइन अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर करमापा ने 11वें पंचेन लामा की कुशलता के लिए प्रार्थना की और यह उम्मीद जताई कि युवा पंचेन लामा को उनकी आध्यात्मिक भूमिको को निभाने की पूरी आज़ादी मिलेगी। गेंधुन छोक्यी निमा की हालत के बारे में अंतिम बयान किसी चीनी अधिकारी का पिछले साल आया था। तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के चीन द्वारा नियुक्त गवर्नर पदमा छोलिंग ने उनके बारे में टिप्पणी की थी। बीजिंग में मार्च, 2010 में चीन के वार्षिक संसद संत्र के बाद पत्रकारों से बात करते हुए छोलिंग ने कहा था, "युवा निमा अपने परिवार के साथ तिब्बत में ही कहीं रह रहे हैं और काफी खुशहाल जीवन जी रहे हैं।" हालांकि, छोलिंग ने उनके बारे में कुछ और विवरण नहीं दिया। इसके बाद पांच तिब्बती एनजीओ के गठबंधन ने अपने बयान में कहा था, "बिना किसी प्रमाण के इस तरह का बयान बेबुनियाद है, जब तक चीन सरकार उनके मौजूद होने का प्रमाण नहीं देती, इसका कोई मतलब नहीं है।" गठबंधन ने मांग की थी कि चीन इस बारे में साफ प्रमाण दे कि उन्हें कहां रखा गया है। परंपरागत रूप से पंचेन लामा का काफी महत्व है क्योंकि वे दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज में भी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसी तरह पंचेन लामा की खोज दलाई लामा करते हैं। कई लोगों का कहना है कि चीन ने इसी वजह से पंचेन लामा को गायब कर एक दूसरे बालक ग्यालत्सेन नोर्बू को खुद ही पंचेन लामा घोषित कर दिया। चीन इस तरह से दलाई लामा के पुनर्जन्म में भी अपना हाथ रखने की कोशिश कर रहा है।

भारत और विदेशों में रहने वाले निर्वासित तिब्बतियों में से 49,000 से ज्यादा लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया और सेंगे ने आसानी से दो अन्य उम्मीदवारों को परास्त कर दिया।

लोबसांग सेंगे बने निर्वासित तिब्बतियों के प्रधानमंत्री

(रेडियो फ्री एशिया, 27 अप्रैल)

हार्वर्ड लॉ स्कॉलर लोबसांग सेंगे को निर्वासित तिब्बती सरकार का नया प्रधानमंत्री चुना गया है और तत्काल ही उन्हें एक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि दलाई लामा ने अपनी राजनीतिक सत्ता चुने हुए नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री को दे दी है। 43 साल के सेंगे को कुल मतदान में से 55 फीसदी मत प्राप्त हुए। मार्च 20 को हुए अंतिम दौर के चुनावों में उन्होंने दो अन्य उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। इस जीत के बाद डॉ. सेंगे ने कहा, "मैं अपने चुनाव को परमपावन दलाई लामा की दूरगामी नीतियों की एक पुष्टि के रूप में और एक पूरी तरह लोकतांत्रिक समाज बनाने की उनकी सोच की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानता हूं। मेरा मानना है कि हाल के कालोन ट्रिपा और चितयु के चुनावों की सफलता और इन चुनावों में तिब्बतियों की सक्रिय भागीदारी हम सबके लिए एक बड़ी नैतिक विजय है।"

दलाई लामा ने कहा, "तिब्बत के भीतर एक तरह का सांस्कृतिक संहार चल रहा है।"

रिपोर्ट में कहा गया है, "कई ऐसी खबरें आई हैं कि निर्वासित तिब्बती समुदायों में घुसपैठ करने और दलाई लामा एवं उनके सहयोगियों पर नजर रखने के लिए चीनी एजेंट खुली भारत–नेपाल सीमा पार कर भारत में पहुंच रहे हैं। मार्च, 2011 में चीन ने घोषणा की कि वह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (साक) के साथ अपने संबंध को और मजबूत करेगा।"

प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में सेंगे ने आरएफए से कहा, "दलाई लामा ने राजनीतिक सत्ता तिब्बती जनता को देने का फैसला किया है, यह सत्ता उसे सौंपी जाएगी जिसे तिब्बती जनता ने उदात्त रूप से अपने निर्वासित सरकार का मुखिया चुना है। हमें परमपावन की आकांक्षाओं और विवके का सम्मान करना होगा और उनके इस निर्णय को लागू करने का रास्ता निकालना होगा।

सेंगे ने कहा, "चीन में हर नागरिक के पास आर्थिक संपदा है, लेकिन उसे राजनीतिक आज़ादी नहीं है, लेकिन तिब्बत में रहने वाले तिब्बती आर्थिक रूप से तो पिछड़ ही गए हैं उन्हें राजनीतिक आज़ादी एवं मानवाधिकार भी हासिल नहीं है। हमें उन्हें इस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि तिब्बत में ज्यादा से ज्यादा आज़ादी के संघर्ष में व्यापक सहयोग हासिल करने के लिए विदेशी सरकारों, संसद, सांसदों और बुद्धिजीवियों तक पहुंच बनाने के लिए निर्वासित तिब्बत सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए। सांगे ने कहा कि वह चीन से वार्ता के लिए परमपावन के मध्यम मार्ग नीति का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, "मैं परमपावन दलाई लामा के घोषित दृष्टिकोण का अनुसरण करूंगा और वह दृष्टिकोण है मध्य मार्ग नीति पर चलना, जिसमें चीन के भीतर ही वास्तविक स्वायत्तता की मांग की गई है। एक निर्वाचित कालोन ट्रिपा के नाते मुझे निर्वासित तिब्बत सरकार की नीतियों को लागू करना है।" सेंगे ने चीन से भी यह आह्वान किया कि वह तिब्बत में अपनी 'कठोर नीतियों' को छोड़े जिसके तहत क्षेत्र में राजनीतिक दमन, सांस्कृतिक विलोपन, आर्थिक हाशियाकरण और पर्यावरण विनाश हो रहा है।

भारत और विदेशों में रहने वाले निर्वासित तिब्बतियों में से 49,000 से ज्यादा लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया और सेंगे ने आसानी से दो अन्य उम्मीदवारों को परास्त कर दिया।

उत्तर–पूर्वी भारत मे चाय उत्पादक इलाके दार्जिलिंग के पास जन्मे एवं पले–बढ़े सेंगे ने उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हासिल की और उसके बाद हार्वर्ड लॉ स्कूल से मास्टर डिग्री हासिल की। वह तब से ही अमेरिका में रह रहे हैं और फिलहाल हार्वर्ड लॉ स्कूल के सीनियर फेलो हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद वह धर्मशाला आ जाएंगे। वे सामदोंग रिनपोछे की जगह ले रहे हैं जो लगातार दस साल तक प्रधानमंत्री रहे। निर्वासित तिब्बतियों के कानून के मुताबिक प्रधानमंत्री का कार्यकाल पांच साल का होता है और कोई व्यक्ति दो बार इस पद पर रह सकता है।

धर्मशाला के कीर्ति मठ के भिक्षुओं ने दिल्ली तक शांति मार्च शुरू किया

(फायूल, धर्मशाला, 27 अप्रैल)

स्थानीय कीर्ति मठ के एक सौ से ज्यादा भिक्षु 26 अप्रैल को धर्मशाला से दिल्ली की ओर पैदल ही शांति मार्च पर निकल पड़े। तिब्बत के आमदो प्रांत में स्थित कीर्ति मठ के अपने साथी भिक्षुओं के प्रति समर्थन जताने के लिए इस मार्च का आयोजन किया गया है। तिब्बत में कीर्ति मठ पर चीनी कार्रवाई का हवाला देते हुए कालोन ट्रिपा प्रोफेसर सामदोंग रिनपोछे ने कहा, "यह काफी महत्वपूर्ण क्षण है और इससे तिब्बती नस्ल, संस्कृति और उसकी विशिष्ट पहचन के पूरी तरह विनाश की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और शांतिप्रिय लोगों से आह्वान किया कि वह चीन को इस बात के लिए राजी करें कि वह जमीनी सच्चाई को समझे और तिब्बतियों को कम से कम बुनियादी मानवाधिकार तो दे। धर्मशाला के कीर्ति जेपा मठ और दार्जिलिंग के सुखे कीर्ति मठ ने पूरी तरह भिक्षुओं के इस शांति मार्च का आयोजन किया है। इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया गया है कि वह चीन पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वह नाबा में जारी बर्बर कार्रवाई को तत्काल रोके।

दलाई लामा ने कहा कि वह 'पूरी तरह आध्यात्मिक गुरू' के तौर पर काम करेंगे

(क्योदो, 30 अप्रैल)

दलाई लामा ने शुक्रवार को कहा कि अपनी राजनीतिक सत्ता निर्वासित तिब्बती सरकार के नए चुने हुए प्रधानमंत्री को सौंपने के बाद ''पूरी तरह आध्यात्मिक गुरू'' के रूप में काम करेंगे।

जापान में 11 मार्च को आए भूकंप और सुनामी से पीड़ितों के लिए टोक्यो के एक मंदिर में प्रार्थना करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "मैंने अपनी सभी वैधानिक राजनीतिक सत्ता एक चुने हुए नेता को सौंपने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दलाई लामा के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने इस बात को साफ किया है कि दलाई लामा की संस्था को पूरी तरह से आध्यात्मिक गुरू, आध्यात्मिक संस्था होना चाहिए।" हार्वर्ड के लॉ स्कॉलर लोबसांग सेंगे के निर्वासित तिब्बती सरकार का प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद यह दलाई लामा का पहला संवाददाता सम्मेलन था।

दलाई लामा पहले ही यह कह चुके हैं कि वे अपनी राजनीतिक सत्ता चुने हुए नेता को सौंपना चाहते हैं। दलाई लामा ने कहा, "अब दशाएं लगभग उपयुक्त हैं, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि अपनी सभी वैधानिक राजनीतिक सत्ता चुने हुए नेता को सौंप दूं। अब ज्यादातर तिब्बती यह समझते हैं मेरा यह निर्णय सही समय पर लिया गया है।"

दलाई लामा ने चीन की इस बात के लिए आलोचना की कि वह तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में लोगों का राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से तिब्बतियों की मौत 'एक तरह की राजनीतिक सुनामी' की वजह से हो रही है। दलाई लामा ने कहा, "तिब्बत के भीतर एक तरह का सांस्कृतिक संहार चल रहा है।"

तिब्बती छात्र संगठन ने भारतीय सांसदों से चीन पर दबाव बनाने का आह्वान किया

(फायूल, 28 अप्रैल)

गत 28 अप्रैल को स्टुडेंट्स फॉर फ्री टिबेट (एसएफटी) ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने हाल में पूर्वी तिब्बत के नाबा में उत्पीड़न को देखते हुए भारतीय संसद सदस्यों को जागरूक करने का एक अभियान शुरू किया है। इस दोतरफा प्रयास में एसएफटी ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को लिखे पत्र में उनसे अनुरोध किया है कि वे भारत सरकार को इस बात के लिए मनाए कि वह चीन पर दबाव डाले। एसएफटी का भारतीय प्रतिनिधिमंडल अब तक इसके लिए राज्यसभा सांसद श्री मोहन सिंह, लोकसभा सांसद श्री सी.एम.छंग, लोकसभा सांसद चौधरी अजीत सिंह, राज्यसभा सांसद श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी और लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह से मिल चुका है।

चीन का नेपाल में कई हित जुड़ा हैः अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट

(इंडियन एक्सप्रेस, 26 अप्रैल)

चीन ने नेपाल में अपनी गतिविधियों में भारी बढ़त की है। इसकी वजह यह है कि वहां उसके 'कई महत्वपूर्ण हित' जुड़े हैं जिनमें तिब्बत शरणार्थियों से लेकर भारत को घेरने की उसकी सामरिक रणनीति तक शामिल है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) द्वारा नेपाल पर जारी एक दुर्लभ रिपोर्ट में कहा गया है, "चीन के नेपाल में कई महत्वपूर्ण हित जुड़े हैं। चीन यह चाहता है कि नेपाल से तिब्बती आंदोलनकारी तिब्बत आंदोलन को न चला सकें। चीन हाल के वर्षों में नेपाल को इस बात के लिए मनाने में ज्यादा सफल हुआ है कि वह वहां निर्वासित तिब्बती समुदाय पर रोक लगाए रखे। चीन ने हाल के वर्षों में दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंध विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता पाई है। कुछ लोग इसे प्रमुखतः आर्थिक अभियान के रूप में देखते हैं तो दूसरे, खासकर भारत के सामरिक हलकों में लगातार यह सोच बढ़ रही है कि चीनी की ये गतिविधियां भू–राजनीतिक उद्देश्यों के साथ हैं।" रिपोर्ट में कहा गया है, "कई ऐसी खबरें आई हैं कि निर्वासित तिब्बती समुदायों में घुसपैठ करने और दलाई लामा एवं उनके सहयोगियों पर नजर रखने के लिए चीनी एजेंट खुली भारत–नेपाल सीमा पार कर भारत में पहुंच रहे हैं।

मार्च, 2011 में चीन ने घोषणा की कि वह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के साथ अपने संबंध को और मजबूत करेगा।" साल 2005 में चीन को सार्क का एक पर्यवेक्षक बनाया गया था।

इनके अलावा उत्तर प्रदेश के नौतनवा और नेपालगंज रोड से नेपाल के भीतर तक तथा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से नेपाल के काकरभित्ता तक के रेलमार्ग शामिल हैं।

चीन के रेलवे विस्तार योजना से भारत सरकार चिंतित

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 17 अप्रैल)

नेपाल सीमा के पास चीन में बिछ रहे रेल लाइनों के जाल पर भारतीय रेलवे गहरी नजर रखे हुए है। अपने रेलमार्ग को ल्हासा से तिब्बत के दूसरे बड़े शहर शिगास्ते तक ले जाने के चीन के निर्णय ने सामरिक वजहों से भारत सरकार के लिए चिंता पैदा कर दिया है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया चीन ल्हासा से शिगास्ते तक रेल लाइन बिछा रहा है। वह इस रेलमार्ग को समूचे तिब्बत–नेपाल सीमा तक फैलाना चाहता है जिसे अंत में काठमांडू तक बढ़ाया जा सकता है। शिगास्ते ल्हासा से करीब 280 किलोमीटर दक्षिण–पश्चिम में है। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार चीन शिगास्ते से न्यालम तक करीब 400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए संभाव्यता अध्ययन कर रहा है। न्यालम से काठमांडू की दूरी सिर्फ 120 किलोमीटर है। भारतीय रेल चीन के रेलमार्ग विस्तार की इस योजना से काफी चिंतित है क्योंकि इससे नेपाल की भारत पर निर्भरता कम हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार काठमांडू तक रेलमार्ग हो जाने के बाद नेपाल सीधे बीजिंग से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करने लगेगा। इसलिए रेलवे ने नेपाल को जोड़ने वाले छह रेल मार्गों और भूटान को जोड़ने वाले तीन रेल मार्गों का निर्माण प्राथमिकता के

वह चीन के एक सुनियोजित मोहरे हैं जो तिब्बत आज़ादी आंदोलन और नेपाली राजनीति, दोनों में घुसपैठ कर चुके हैं।

(1)

Panel discussion after His Holiness the Dalai Lama's lecture in honor of former Indian President R. Venkataraman on 'Non Violence and Spiritual Values in a Secular India' in New Delhi, India, on April 2nd, 2011. Photo/Tenzin Choejor/OHHDL

(2)

(10)

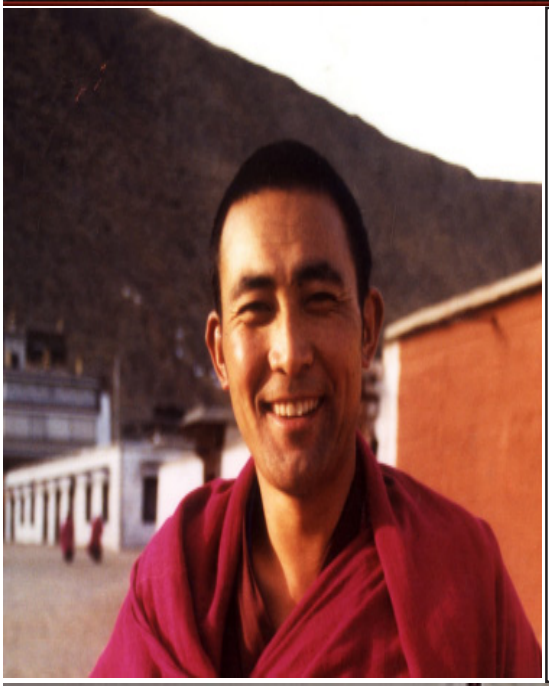

कैमरे की

1. नई दिल्ली में 2 अप्रैल, 2011 को पूर्व भारतीय राष्ट्रपति आर. वेंकटरामण के आयोजित एक व्याख्यान को संबोधित करते परमपावन दलाई लामा।
2. 'धर्मशाला में 11 अप्रैल, 2011 को कालोन ट्रिपा प्रोफेसर सामदोंग रिनपोछे, चार्टर में उस संशोधन का प्रारूप सौंपते हुए जिसके द्वारा परमपावन दलाई
3. धर्मशाला में 22 अप्रैल, 2011 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) द्वारा दीघ
4. कीर्ति मठ के भिक्षुओं के लिए प्रार्थना सभा की अध्यक्षता करते परमपावन द
5. निर्वाचित कालोन ट्रिपा डॉ. लोबसांग सेंगे ने 27 अप्रैल को अमेरिका के वाशिं फोटोः रायटर्स
6. मंगलवार, 26 अप्रैल, 2011 को शांति मार्च के लिए जुटे (बाएं से) डिप्टी स्पीक तिब्बती संसद के सदस्य।
7. एक शांति मार्च में शामिल होते भिक्षु और आम लोग।
8. नई दिल्ली में 25 अप्रैल, 2011 को चीन के सिचुआन प्रांत के गवर्नर के आ
9. तिब्बती युवा कांग्रेस के तीन सदस्य (बाएं से दाएं) कोनछोक यांगफेल, धोनडु 2011 को नई दिल्ली के जंतर–मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कि
10. जामयांग जिंपा : फाइल फोटो

(9)

(8)

♦ आंखों देखी

(3)

(4)

आंख से

सम्मान में ''धर्मनिरपेक्ष भारत में अहिंसा और आध्यात्मिक मूल्य'' विषय पर

प्रारूप समिति के सदस्य (बाएं से दूसरे) संसद के महासचिव (बाएं से पहले) को
लामा के राजनीतिक अधिकार चुने हुए नेतष्त्व को सौंपा जाएगा।
ायु के लिए आयोजित समारोह में पहुंचते परमपावन दलाई लामा।
लाई लामा।
गटन स्थित अंतरराष्ट्रीय तिब्बत अभियान (आईसीटी) के कार्यालय का दौरा किया।

र डोलमा ग्यारी, स्पीकर पेनपा सेरिंग, कालोन ट्रिपा, कीर्ति रिनपोछे और निर्वासित

गमन का विरोध करते तिब्बती युवा कांग्रेस के सदस्य।
प ल्हडार और तेनजिन नॉरसंग ने नाबा में चीनी कार्रवाई के विरोध में 25 अप्रैल,
या।

(5)

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(7)

(6)

देंग की घोषणा के मुताबिक ही माओवादियों के इस तरीके को रोक दिया गया।

आधार पर करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार नेपाल तक जाने वाले छह रेल मार्गों में बिहार के रक्सौल, जोगबनी और जयनगर से नेपाल के बीरगंज, बिराट नगर और बर्दीबास तक के रेलमार्ग शामिल हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के नौतनवा और नेपालगंज रोड से नेपाल के भीतर तक तथा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से नेपाल के काकरभित्ता तक के रेलमार्ग शामिल हैं। फिलहाल भारत से नेपाल के भीतर तक जाने वाला सिर्फ एक रेलमार्ग जयनगर से जनकपुर तक शामिल है।

नेपालः चीन का सबसे बड़ा विश्वासघात

(यूरेशिया रीव्यू, 27 अप्रैल)

भास्कर रॉय

विरोधी राजाओं के दरबार में अपने एजेंट घुसा देने की चीन की यह मौन युद्ध रणनीति करीब छठी सदी से चल रही है। यह रणनीति 'छलघाती गदा' के नाम से लोकप्रिय है। इसका बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है।

जब नेपाल के प्रधानमंत्री झाला नाथ खनाल (जो सीपीएन–यूएमएल के अध्यक्ष भी हैं) ने यूएमएल –यूसीपीएन (माओवादी) सरकार में ल्हार क्याल लामा को वित्त राज्य मंत्री बनाया तो कई नेपाली राजनीतिज्ञों और काठमांडू की चीन समर्थक लॉबी के दिल में लाल झंडा फहरने लगा। दिलचस्प यह है कि ल्हार क्याल लामा की नियुक्ति के एक पखवाड़े पहले ही चीन की जनमुक्ति सेना के प्रमुख जनरल चेन बिंगदे के नेतृत्व में चीनी सेना का एक 15 सदस्यीय दल नेपाल के दौरे पर आया था। इस दल ने राष्ट्रपति राम बरन यादव, प्रधानमंत्री खनाल, नेपाल की थल सेना के प्रमुख छत्र मान सिंह गुरुंग और प्रतिरक्षा से जुड़े अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने नेपाली सेना के गैर प्रतिरक्षा परियोजनाओं को 3 करोड़ युआन की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

इस प्रतिनिधिमंडल की संरचना और जनरल छेन की अपने नेपाली समकक्षों के साथ होने वाली बातचीत काफी गौर करने वाली है। उन्होंने तिब्बत की सुरक्षा पर बात की। उन्होंने यह साफ किया कि चीन किसी भी तरह से 'नेपाल–चीन संबंधों के द्विपक्षीय पहलू में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी को बर्दाश्त नहीं करेगा।' इसकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि नेपाली नेताओं को यह चेतावनी दी गई है कि वे अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों को नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों की मदद से तिब्बत को अस्थिर करने के अभियान चलाने के लिए नेपाली जमीन के इस्तेमाल का कोई मौका न दें।

इसके अलावा नेपाली मीडिया के अनुसार काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने ल्हार क्याल लामा की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री खनाल और यूएमएल के अन्य नेताओं से 'औपचारिक' तौर पर विरोध जताया है। लामा की नियुक्ति विस्मित करने वाली बात है, यह देखते हुए कि चीन सरकार और काठमांडू स्थित चीनी दूतावास तिब्बती शरणार्थियों के किसी छोटे प्रदर्शन पर भी बेहद कड़ाई से पेश आते हैं। नेपाल ने हाल में निर्वासित तिब्बतियों को निर्वासित तिब्बती सरकार के कालोन ट्रिपा यानी प्रधानमंत्री के चुनाव में भी शामिल होने से रोक दिया था। और अब नेपाल ने उन लामा को मंत्री बनाया है जो तिब्बत की आज़ादी का झंडा बुलंद किए हुए हैं।

नेपाल में चीन की साजिश और नेपाली जनता के साथ विश्वासघात का खुलासा 20 अप्रैल को एक स्थानीय अखबार कांतिपुर ने किया जब उसने लामा की गतिविधियों का ब्यौरा दिया। वह चीन के एक सुनियोजित मोहरे हैं जो तिब्बत आज़ादी आंदोलन और नेपाली राजनीति, दोनों में घुसपैठ कर चुके हैं। वित्त राज्य मंत्री के रूप में वह चीन के समर्थन में नीतियां बनवा सकेंगे और सरकार की आंतरिक नीतियों एवं सोच की जानकारी चीन को दे सकेंगे। खबर के अनुसार वह काठमांडू स्थित चीनी दूतावास में स्थित चीनी सेना के अटैची ऑफिस के आधिकारक सूत्र हैं।

ल्हार क्याल लामा को झाला नाथ खनाल का करीबी माना जाता है। जनलर छेन बिंगदे के नेपाल दौर के ठीक बाद उनकी नियुक्ति कोई अचरज की बात नहीं है क्योंकि खनाल को चीन का करीबी माना जाता है। इसलिए विवादित पृष्ठभूमि वाले ल्हार क्याल लामा की ऐसे ऊंचे स्थान पर नियुक्ति से यह समझा जाता है कि नेपाली जनता के पीठ पीछे खनाल और चीन ने हाथ मिला लिया है।

नेपाली अखबार रिपब्लिका ने लामा का पिछला इतिहास खंगाला है। उनके पास मौजूदा नाम से नेपाली पासपोर्ट है, 12 जून,1998 को गुवाहाटी से जारी खेनसो छिमे सेरिंग नाम से भारतीय पासपोर्ट और भारत में 1969 में लामा छिमे सेरिंग के नाम से बना तिब्बती शरणार्थी पहचान पत्र भी है। वह धोखाधड़ी जैसी कई तरह की सवालिया गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

वह किसी देश के खुफिया एजेंट बनने के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार हैं। विरोधी राजाओं के दरबार में अपने एजेंट घुसा देने की चीन की यह मौन युद्ध रणनीति करीब छठी सदी से चल रही है। यह रणनीति 'छलघाती गदा' के नाम से लोकप्रिय है। इसका बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। छलघाती वह एजेंट होता है जिसे विरोधी के सत्ता केंद्र में घुसपैठ करा दिया जाता है, गदा एक मौन हथियार होता है, इस तरह से एजेंट चुपचाप आसपास के वातारण में

घुल–मिल कर काम करता है। नेपाल में चीन का एक छलघाती गदा उजागर हो चुका है। अभी ऐसे कितने हैं, इसके बारे में कुछ कह पाना कठिन है, लेकिन यह तो निश्चित है कि चीन ऐसे सिर्फ एक एजेंट पर निर्भर नहीं है।

चीन की एक प्राचीन रणनीति यह भी रही है कि दुश्मन का दुश्मन सामरिक दोस्त होता है और उसे अपने साथ जोड़ना चाहिए। यह चीन के पड़ोसियों के लिए एक परेशान करने वाला संकेत हो सकता है कि चीन उन्हें कमजोर करना चाहता है। माओत्से तुंग का युग खत्म होने के बाद चीन के प्रमुख नेता और चीन में आधुनिकीकरण के जनक डेंग जियोपिंग ने साफ तौर पर यह घोषित किया कि दूसरे देशों में जनक्रांति को समर्थन देने की माओ की रणनीति गलत थी और उसे त्याग दिया जाएगा। देंग की घोषणा के मुताबिक ही माओवादियों के इस तरीके को रोक दिया गया। लेकिन माओ की रणनीति के मुख्य हिस्से को एक ज्यादा परिष्कृत रणनीति में बदल दिया गया। उल्फा, नगा अलगाववादियों (एनएससीएन–आईएम) और उत्तर–पूर्व के कई अलगाववादी संगठनों को चीनी सेना द्वारा हथियार, गोला–बारूद, संचार उपकरण और अन्य सहयोग देने से इस रणनीति का खुलासा हो गया है। हालांकि अभी इसके ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि चीन 'कट आउट्स' के द्वारा खुफिया शैली में काम कर चुका है। इन कट्आउटस में पाकिस्तान की आईएसआई, बांग्लादेश की भारत विरोधी सरकारें और हथियारों का कारोबार करने वाली ऐसी चीनी कंपनियां शामिल रही हैं जिनकी गतिविधियों के बारे चीन अनभिज्ञता प्रकट कर सकता है।

यह बड़ा सवाल उठाया जा रहा था कि क्या चीन के उन माओवादियों से रिश्ते वाकई खराब हो चुके थे, जब वे राजशाही के खिलाफ लड़ने के लिए भूमिगत हो गए थे। लेकिन चीन और नेपाली माओवादी, खासकर प्रचंड–वैद्य समूह ने जिस तरह से साथ मिलकर एक कटु भारत विरोधी सरकार बनाने के लिए कार्य किया उससे यह पता चलता है कि चीन का माओवादियों के साथ तार्किक लेकिन गहरा रिश्ता है। सत्ता से बाहर कर दिए गए नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र अब इस बात को समझ रहे होंगे कि चीन ने उनकी पीठ में भी छूरा घोंपा हैं। या चीन उनके साथ अब भी तालुक्कात की खिड़की खुली रखना चाहता है। पुराने माओवादियों की तरह ज्ञानेंद्र भी अब भारत की ज्यादा यात्रा करते हैं और वह अब चीन के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते। इस बात का विवरण देने की जरूरत नहीं है कि चीन किस तरह से नेपाल में खेल कर रहा है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि चीन नेपाली माओवादियों के माध्यम से भारतीय माओवादियों तक संपर्क बना चुका हो। चीनी खुफिया के आर–पार बिछे जाल ने नेपाली माओवादियों को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है कि वे जनता में अपनी विश्वसनीयता खोए बिना इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। माओवादियों के रवैए को अब नेपाली जनता इस रूप में देख रही है कि वे देश को चीन के हाथों बेच रहे हैं।

झल नाथ खनाल सहित यूएमएल में चीन समर्थक मजबूत लॉबी के बारे में भी कुछ ऐसी ही सोच है। अब चीन यह समझ चुका है कि उसने खुद ही पूर्वी पड़ोसियों के साथ ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे केवल अशांति और चीन के धमकी भरे व्यवहार के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में मजबूत गठबंधन ही तैयार हो सकता है।

नेपाल में हो रहे जटिल घटनाक्रम के बारे में भारत को सचेत रहना चाहिए जिस पर साउथ ब्लॉक (भारत के गृह मंत्रालय) और पीएमओ को भी ध्यान देना होगा। लेकिन भारत यदि चीन पर भरोसा कर गफलत में रहता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। चीन के सामरिक जाल से साधारण प्रतिक्रिया से नहीं निपटा जा सकता।

"चीन और पाकिस्तान के बीच हमेशा के लिए रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को मजबूत करना और आगे बढ़ाना हमारा साझा सामरिक विकल्प है।"

नियंत्रण रेखा पर चीनी घुसपैठ के बारे में भारत को चेतावनी

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 6 अप्रैल)

भारतीय थल सेना के एक शीर्ष जनरल ने चेतावनी दी है कि भारत न केवल चीन से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी घुसपैठ के खतरे का सामना कर रहा है, बल्कि यह खतरा आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान से मिलने वाली नियंत्रण रेखा (एलओसी) तक पहुंच सकता है क्योंकि चीन और पाकिस्तान में सैन्य गठजोड़ बढ़ता जा रहा है। करीब 4,057 किलोमीटर लंबे एलएसी पर, खासकर तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और पाक अधिकृत कश्मीर में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में चीनी दखल बढ़ना अब साफ हो गया है।

लेकिन पहली बार भारतीय सेना के किसी शीर्ष कमांडर ने चीन की जनमुक्ति सेना के जवानों के घुसपैठ के बारे में सार्वजनिक तौर पर आशंका जाहिर की है। यह जवान 778 किलोमीटर लंबी भारत–पाकिस्तान की संवेदनशील नियंत्रण रेखा के

अपने आगे बढ़ने के साथ ही वह हमारे राजनयिक तुष्टीकरण पॉस्टर्स और प्रतिरक्षा की कमजोरियों का दोहन करेगा।

जमीनी स्तर पर देखें तो यह परंपरा शताब्दियों पुरानी है और यही भारत की असली ताकत है।

पास भी पहुंच गए हैं। जम्मू में आयोजित एक सेमिनार में थल सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पराणिक ने कहा, "भारत की सेना के लिए न केवल चीन सीमा पर बल्कि पाकिस्तान से लगने वाली नियंत्रण रेखा पर भी चुनौती पैदा हुई है। हम अब कई लोगों को यह चिंता जताते हुए देख रहे हैं कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी बैर हुआ तो चीन की इसमें क्या भूमिका होगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि चीन हमारा पड़ोसी है, बल्कि इसलिए वास्तव में उनके सैनिक अब पाकिस्तान से लगने वाली नियंत्रण रेखा तक भी पहुंच गए हैं और वहां जमे हुए हैं।"

चीन–पाक दोस्ती का भारत के लिए निहितार्थ

(हिंदुस्तान टाइम्स, 7 अप्रैल)

उन्होंने कहा, "इस देश में अब तक हजारों साल से विभिन्न तराह के मतों का विकास हुआ है और यह यहां के बौद्ध, इस्लाम, इसाइयत और सिख जैसे विभिन्न दर्शनों में आत्मसात है।

दो साल पहले रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि, ''भारत के सुदूर सीमा पर चीन और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा जमाए गए इलाके में इन दोनों देशों के सैनिकों का साथ जुटने का भारत पर सीधा सैन्य असर हो सकता है।" यह कुछ हद तक सच साबित हुआ जब पिछले हफ्ते थल सेना के उत्तरी कमान के मुखिया ने इस बात की पुष्टि की कि चीनी सेना नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान में मौजूद है। इन चीनी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर हमारी तरह कोई बंदूकें नहीं तैनात कर रखी हैं, लेकिन वे पाकिस्तान में रहकर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के साथ मिल कर काम कर रहे हैं उससे पता चलता है कि उनका कोई संयुक्त हित है और वे अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाने के साथ ही युद्ध करने की तैयारी को भी बढ़ा रहे हैं। उत्तरी कमांडर ने जो कुछ भी कहा है वह नया नहीं है। चीन की सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित – बाल्टिस्तान क्षेत्र में मौजूद है। कहने के लिए तो चीनी सेना काराकोरम राजमार्ग के मरम्मत, सुधार और नए सिरे से उसे चालू करने के लिए वहां पर है। करीब एक साल पहले से वहां चीनी सेना देखी जा रही है। यह भी पता चला है कि चीन सीक्यांग के कशगर से पाकिस्तान के ग्वादर प्रांत तक रेल मार्ग और तेल पाइप लाइन बिछाने की तैयारी कर रहा है।

चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने दिसंबर, 2010 में पाकिस्तानी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा था, "चीन और पाकिस्तान के बीच हमेशा के लिए रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को मजबूत करना और आगे बढ़ाना हमारा साझा सामरिक विकल्प है।" वेन के इस संबोधन के बाद मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने इसे 'पाकिस्तान के दुश्मनों' के लिए एक कड़ा संदेश बताया।

भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत–चीन सीमा 4,056 किलोमीटर लंबी है। इसमें अक्साई चिन, पीओके और शाक्सगम घाटी सहित समूचा पश्चिमी क्षेत्र भी शामिल है। शाक्सगम घाटी को मार्च 1963 को एक समझौते के द्वारा पाकिस्तान ने चीन को उपहार में दे दिया। हालांकि, 14 दिसंबर, 2010 को चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स को दिए एक बयान में चीन स्थित भारतीय राजदूत ने न जाने किस वजह से भारत–चीन सीमा की लंबाई 3,488 किलोमीटर ही बताई। इस इंटरव्यू को प्रकाशित करते समय अखबार ने अपनी टिप्पणी में लिखा है, "भारत–चीन के बीच साझा सीमा कितनी लंबी है अभी इसका निपटारा नहीं हुआ है। चीन सरकार अक्सर इस सीमा को 2,000 किलोमीटर लंबी बताती है।" इस प्रकार सीमा रेखा की लंबाई कम करके चीन सरकार जम्मू–कश्मीर पर भारत के प्रभुत्व पर सवालिया निशान लगाती है।

तिब्बत और हिंद महासागर में भारत एवं चीन के बीच सुरक्षा और संप्रभुता के अन्य संबंधित मसलों पर विस्तार से जाए बिना भी यह बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि जैसे–जैसे चीन भू–राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से ज्यादा ताकवर होता जाएगा वह ज्यादा आक्रामक होगा और सीमा विवाद पर ज्यादा दबाव बनाएगा। सुरक्षा और सैन्य संबंधी मसलों पर चीन अपनी एसर्टिव राजनय के लिए जाना जाता है। अपने आगे बढ़ने के साथ ही वह हमारे राजनयिक तुष्टीकरण पॉस्टर्स और प्रतिरक्षा की कमजोरियों का दोहन करेगा। भारत–चीन की आर्थिक और सुरक्षा संबंध विपरीत ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं।

तिब्बती हिमनदियों का पिघलना चिंता का विषयः दलाई लामा

(एपी, 4 अप्रैल)

परमपावन दलाई लामा ने कहा है कि तिब्बत पठार में हिमनदियों के पिघलने से भारत को गंभीर चिंता होनी चाहिए क्योंकि भारत के करोड़ों लोग यहां से आने वाले पानी का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने चीनी विशेषज्ञों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि तिब्बत की हिमनदियां दुनिया में किसी भी अन्य जगह के मुकाबले तेजी से पिघल रही हैं। उन्होंने तिब्बत की पारिस्थितिकी पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "यह बहुत–बहुत जरूरी है।"

हिमनदियों को एशिया की सिंधु और गंगा सहित कई एशियाई नदियों की महत्वपूर्ण जीवनरेखा माना जाता है। इन हिमनदियों के खत्म हो जाने से इन क्षेत्रों में जल आपूर्ति को खतरा पैदा हो जाएगा। नई दिल्ली में करीब 400 भारतीय लोगों को एक समारोह में संबोधित करते हुए दलाई लामा ने कहा, "करोड़ों भारतीय हिमालय से आने वाली हिमनदियों के पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको तिब्बत पठार की पारिस्थतिकी के बारे में अपनी चिंता जताने का अधिकार है। उन्होंने कहा, "भारत एक आज़ाद देश है, मुझे लगता है कि उसे इस मसले पर ज्यादा गंभीर चिंता दिखानी चाहिए जो कि मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसका राजनीति से कोई लेना–देना नहीं है और यह चीनी जनता सहित सबके हित की बात है।"

युवा भारतीयों को अहिंसा के मूल्यों को संरक्षित रखना चाहिएः दलाई लामा

(इंडियन एक्सप्रेस, 2 अप्रैल)

तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का मानना है कि शताब्दियों की ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े भारतीय युवाओं को अपने अहिंसा के मूल्यों के संरक्षण में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और इसे दुनिया भर में प्रचारित भी करना चाहिए।

भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत ही है जिसने उन्हें लोकतंत्र के सही अर्थ से परिचित कराया और युवा भारतीयों को भी विभिन्न संस्कृतियों के मेल से हजारों सालों में विकसित अपनी समृद्धि सांस्कृतिक परंपराओं को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "अहिंसा और आध्यात्मिकता के बारे में मेरे पास भारतीय लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है, आप तो करीब 2000 साल से इन सब चीजों को जानते हैं।" पूर्व राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण की जन्म शताब्दी के अवसर पर नेहरू स्मारक संग्रहालय में चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित संगोष्ठी 'भारत में अहिंसा और आध्यात्मिकता' में लोगों को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने यह बात कही। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से मुलाकात को याद करते हुए परमपावन दलाई लामा ने कहा वह मुझे नाराज किए बगैर मेरी बातों से असहमत हो सकते थे, यह भारत में स्वस्थ आलोचना की एक परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने नेहरू से मुलाकात को याद करते हुए कहा, "1950 के दशक में नेहरू के साथ दिल्ली में एक मुलाकात के दौरान हम एक बिंदु पर आकर कुछ मसलों पर असहमत हो गए। इसके बाद जब मैं दुबारा उनसे मिला मैं कुछ आशंकित था, लेकिन मैंने देखा कि वे बिल्कुल सामान्य थे।"

उन्होंने कहा, "मेरे विचार से चीन में नेता ऐसे नहीं हैं। मैंने करीब नौ साल तक चीनी नेतृत्व से निपटने में यह अनुभव किया है। हालांकि जनरल माओत्से तुंग इस मामले में थोड़े अपवाद थे, लेकिन इसके बाद मैंने यह पाया है कि वहां के नेताओं के शब्द जमीनी सच्चाई में तब्दील नहीं होते या लागू नहीं होते।"

दलाई लामा ने बताया कि भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने उनसे एक बार कहा था कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता इस वजह से है क्योंकि यहां हजारों साल से आलोचना की परंपरा है। उन्होंने कहा, "इस देश में अब तक हजारों साल से विभिन्न तराह के मतों का विकास हुआ है और यह यहां के बौद्ध, इस्लाम, इसाइयत और सिख जैसे विभिन्न दर्शनों में आत्मसात है। जमीनी स्तर पर देखें तो यह परंपरा शताब्दियों पुरानी है और यही भारत की असली ताकत है। खुद को 'भारत के प्राचीन विचारों का संदेशवाहक' और भारत के साथ अपने रिश्ते को 'गुरू एवं चेले' बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों को अपनी परंपरा में निहित अहिंसा के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने युवा भारतीयों से यह भी आह्वान किया कि वे समाज की बुराइयों को दूर करने पर ज्यादा ध्यान दें जैसे–जातिवाद, दहेज प्रथा और समाज में व्याप्त अन्य तरह के भेदभाव। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आर्थिक प्रगति में चीन से भारत पीछे हो, लेकिन अपने समृद्ध लोकतांत्रिक और आज़ादी के मूल्यों की वजह से भारत दुनिया में ज्यादा सकारात्मक और प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

दलाई लामा दुनिया के 100 प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं में भामिल

(वायस ऑफ अमेरिका, 7 अप्रैल)

दलाई लामा को लंदन की एक पत्रिका वाटकिंस रीव्यू ने दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावी आध्यात्मिक नेता माना है। दुनिया की 100 प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं की इस सूची में लेखक दीपक चोपड़ा पांचवें, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला 19वें और पोप 34वें स्थान पर हैं। बेस्ट सेलिंग

सोना खनन करने वालों ने न केवल यहां के अल्पाइन वृक्षों और जैवविविधता को नष्ट किया है बल्कि उन्होंने इस पवित्र स्थल की पवित्रता को भी नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय लोगों ने लगातार सोना खनन करने वालों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार के स्थानीय अधिकारियों के कान पर अभी तक जूं भी नहीं रेगा।

बीजिंग से भेजे गए अमेरिकी दूतावास के केबल के विकीलीक्स द्वारा खुलास

लेखक एकाहार्ट टोले को इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। वाटकिंग रीव्यू की प्रकाशन और बिक्री इंग्लैंड के सबसे पुराने बुकशॉप वाटकिंस बुक्स द्वारा की जाती है। यह पत्रिका चीन के अलावा दुनिया भर में एप्पल के एप्लिकेशन स्टोर में भी उपलब्ध है। दलाई लामा की तारीफ होने की वजह से चीन ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है।

अंधाधुंध सोना उत्खनन से तिब्बत में मानव जीवन, पारिस्थितिकी को खतरा

(टिबेट डॉट नेट, 28 अप्रैल)

आग की लपटों में जलते हुए वह चिल्लाते रहे, "दलाई लामा को वापस आने दो" "तिब्बत को आज़ाद करो", दलाई लामा दीर्घायु हों। यह सब देखकर अचानक चकित रह गए लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई,

उत्तर–पूर्वी तिब्बत के रेबकांग में स्थित एक पवित्र पर्वत के पास स्थित स्वर्ण भंडार से हो रहे अंधाधुंध उत्खनन से वहां से बहने वाली नदियों में भारी प्रदूषण हो रहा है। इन नदियों के जल का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय तिब्बतियों का कहना है कि उनके जीवन और इलाके की पारिस्थतिकी को भारी खतरा है। रेबकांग के कु–दे कारोंग में कई पीढ़ियों से पवित्र माने जाने वाले पहाड़ से निकलने वाली गु छु नदी के जल का इस्तेमाल रेबकांग के सभी हिस्सों के तिब्बती और उनके मवेशी करते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से इस नदी के ऊपरी धारा में चीन सरकार द्वारा लगातार जहर घोलने से इन लोगों का जीवन खतरे में आ गया है। स्थानीय तिब्बतियों का कहना है कि खनन का काम अब भी जारी है। इस पवित्र पर्वत पर तीर्थयात्रियों के लिए नौ अलग–अलग पूजा स्थल और दो पवित्र गुफाएं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई पीढ़ियों से इस पवित्र पहाड़ को पूजा जाता है क्योंकि इसे एक देवता का निवास स्थल माना जाता है। सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सोना खनन करने वालों ने न केवल यहां के अल्पाइन वृक्षों और जैवविविधता को नष्ट किया है बल्कि उन्होंने इस पवित्र स्थल की पवित्रता को भी नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय लोगों ने लगातार सोना खनन करने वालों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार के स्थानीय अधिकारियों के कान पर अभी तक जूं भी नहीं रेगा। इसका उलटा नतीजा निकला और शिकायत करने वालों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। सूत्रों के अनुसार 45 साल के सेवांग क्याप, 50 साल के छिलो ग्याल, 45 साल के ड्रा–टेक और 39 साल के ल्हा–गो ग्याल को गलत आरोप लगाकर दो साल तक मुकदमा चलाया गया और आखिरकार उन्हें जेल में डाल दिया गया। लामा क्याब और नाम के दो अन्य लोग पुलिस से छिपते फिर रहे हैं, लेकिन अपने गांव से बचकर भागने की कोशिश कर रहे एक अन्य नागरिक शाओ ग्याल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ एक स्थानीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है।

करमापा ने लेह का दौरा किया, बादल फटने से प्रभावित लोगों का सांत्वना दिया

(आईएएनएस, 23 अप्रैल)

17वें करमापा ओग्येन ट्रिनली पिछले साल जम्मू–कश्मीर के लेह में आए प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों से जब मिले तो द्रवित हो गए। करमापा के आधिकारिक प्रवक्ता डेकी छुंगयाल्पा ने बताया, "करमापा ने अपने तीन दिवसीय दौरे के अंतिम दिन 20 अप्रैल को बादल फटने से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना जताई।" उन्होंने प्रवचन देने और धार्मिक समारोहों में शामिल होने के लिए कई मठों का दौरा किया। छंगयालपा ने कहा कि करमापा ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और विशेष आशीर्वाद समारोह आयोजित किए। उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित शहर के इलाकों मानेतसाल्डिंग और सैबू का दौरा किया। गौरतलब है कि पिछले साल 6 अगस्त को बादल फटने से लेह शहर के छोगलमसर गांव में भारी बाढ़ और भू स्खलन हुआ था जिससे सरकारी कार्यालय, सुरक्षा बलों के शिविर और बहुत से मकान बह गए थे। इस दैवी आपदा के एक महीने बाद परमपावन दलाई लामा ने भी इस इलाके का दौरा किया था और प्रभावित लोगों से मिले थे।

तिब्बत का लोकतंत्र चीन के लिए दुविधा

(यूरेशिया रीव्यू, 25 अप्रैल)

श्रीकांत कोंडापल्ली

ळालांकि दलाई लामा पहले भी कई अवसरों पर यह संकेत दे चुके हैं, कि वे 'अपनी औपचारिक सत्ता निर्वासित तिब्बती नेता को सौंप देंगे', इसके बावजूद 10 मार्च, 2011 को जारी उनके बयान ने चीनी नेतृत्व की अनभिज्ञता को साबित किया है। यह बयान उस मौके के 10 दिन पहले आया है जब तिब्बती निर्वासित समुदाय अपना नया प्रधानमंत्री और निर्वासित तिब्बती संसद के अन्य सदस्यों का चयन करने जा रहा है। कई वजहों से दलाई लामा के इस कदम का चीन पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक असर पड़ सकता है।

पहली बात तो यह है कि निर्वासित तिब्बती

प्रतिनिधि को सत्ता सौंपने के प्रस्ताव का चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर दूरगामी असर होगा। ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, बहरीन, लीबिया और अन्य देशों में जारी जन अशांति को देखते हुए लोकप्रिय तरीके से निर्वासित संसद को कार्यकारी शक्तियां सौंपने का दलाई लामा के कदम से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में भी इसी तरह की मांग को बढ़ावा मिल सकता है। चीन सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह इस चुनौती का सामना गहर आंतरिक नियंत्रण तंत्र के द्वारा करेगी। इसके पहले राष्ट्रपति जियांग जेमिन के समय में देश में पार्टी के व्यापक पकड़ को बनाए रखने के लिए ''तीन प्रतिनिधित्व वाली रणनीति (पार्टी व्यापक जनता, उत्पादक ताकतों और उन्नत संस्कृति का प्रतिनिधित्व करे) का सुझाव दिया गया था। चीन ने सुधार प्रक्रिया को तेज करने के लिए गांव–गांव तक चुनाव कराने का भी प्रयोग किया, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व देश में ऊपर के स्तर से होता है। इसके अलावा पार्टी का रवैया ऊपर से नीचे के नेतृत्व का ही बना हुआ है और इसकी वजह से वहां लगातार कई लोकप्रिय जनांदोलन हुए जैसे साल 1989 के टिनामेन चौक पर हुई घटना जिसमें करीब 20 लाख विद्यार्थी, श्रमिक और किसानों ने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया था। दूसरी बात, निर्वासित तिब्बतियों के लिए दीर्घकालिक एंव स्थायी सांस्थानिक व्यवस्था और लोकप्रिय जवाबदेही प्रदान कर दलाई लामा ने अपने न रहने की स्थिति में किसी भी तरह की अस्थिरता और अव्यवस्था की संभावना को खत्म कर लिया है। चीनी प्रशासन द्वारा अगला दलाई लामा चुनने के साफ इरादे को देखते हुए दलाई लामा के मौजूदा कदम से यह संभावना भी बेहद कम हो गई है कि अगले दलाई लामा के पास ऐसी कोई सत्ता रहे जो उन्हें निर्वासित तिब्बतियों के 1991 के चार्टर से हासिल हुई थी।

तीसरी बात, हाल के दिनों में चीनी नेताओं के दलाई लामा पर शब्दबाण ज्यादा व्यक्तिगत होते जा रहे हैं और सत्ता त्यागने के दलाई लामा के कदम से चीनी प्रशासन का ध्यान दलाई लामा पर से हट सकेगा। इस प्रकार दलाई लामा के मौजूदा निर्णय से चीनी प्रशासन को अपना केंद्रबिंदु बदलना पड़ेगा और यह संभव है कि अब तिब्बतियों के चुने हुए नेता चीनी आलोचना का लक्ष्य बन जाएं। हालांकि, चीनी नेताओं ने इस बात को दुहराया है कि दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली वार्ता दलाई लामा के व्यक्तिगत भविष्य को लेकर ही होगी और इसमें तिब्बत में शासन प्रणाली पर बात नहीं होगी। ऐसी स्थिति में चीनी अधिकारियों की आलोचना का उन पर ही पलटवार हो सकता है जैसा कि ताइवान में 1995–96 और साल 2000 के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री झू रोंगजी सहित अन्य सर्वोच्च चीनी नेताओं द्वारा कटु आलोचना का नतीजा देखा गया था। इसके अलावा, चीन सरकार और दलाई लामा के प्रतिनिधियों की नौ दौर तक चली अब तक की वार्ताओं का कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है। बीजिंग से भेजे गए अमेरिकी दूतावास के केबल के विकीलीक्स द्वारा खुलासे से पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के ज्यादातर सदस्य यह चाहते हैं कि तिब्बत में अशांति पर कठोर रवैया बनाए रखा जाए। इस उद्देश्य से चीनी अधिकारियों ने चीनी प्रशासन ने तिब्बती भिक्षुओं को बदलने के लिए राजनीतिक शिक्षण अभियान शुरू किए हैं और विद्रोहियों के दमन के लिए ''स्ट्राइक हार्ड'' की नीति शुरू की है। इसका परिणाम यह हुआ है कि तिब्बत और उससे बाहर रहने वाले तिब्बती में राजनीतिक अलगाव और बढ़ा है जिसका निहितार्थ यह है कि तिब्बतियों और चीनियों के बीच संबंध भविष्य में भी कठिन बने रह सकते हैं।

17 मार्च को सुबह 3 बजे फुंशोग का निधन हो गया। वह 1991 में जन्मे थे यानी सिर्फ 20 साल की उम्र के थे। उनके माता–पिता नाबा काउंटी में स्थित मेउरामा टाउनशिप में स्थित एक गांव से थे।

आत्मदाह करने वाले तिब्बती भिक्षु को याद किया गया

(हाईपीकसप्योरअर्थ डॉट कॉम, 26 अप्रैल)

वूएजर

16 मार्च, 2008 को जब भिक्षु और आम लोग तिब्बत के आमदो प्रांत में स्थित नाबा की सड़कों पर उतर आए और विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी तब कई लोग मारे गए जिनमें एक गर्भवती महिला, एक पांच साल का बच्चा और मिडल स्कूल की 16 साल की छात्रा ल्हुनड्रुप सो शामिल थे। इसके तीन दिन के बाद बहुत से तिब्बतियों ने मारे गए लोगों की याद में मंदिरों और घरों में घी के दिए जलाए। इस घटना से दुःखी होकर कीर्ति मठ के एक भिक्षु फुंत्सोग ने खुद को आग लगा कर जान दे दी।

एक चटक दोपहरी में वह उस मठ से बाहर निकला जिस पर सैन्य पुलिस की गहरी निगरानी चल रही थी। वह पैदल सड़क के अंतिम छोर तक गया और अचानक उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। आग की लपटों में जलते हुए वह चिल्लाते रहे, "दलाई लामा को वापस आने दो" "तिब्बत को आज़ाद करो", दलाई लामा दीर्घायु हों। यह सब देखकर अचानक

इसलिए तिब्बती जनता के दमन के दिन की याद करने वाले 16 मार्च को लोग हमेशा 20 साल के भिक्षु फुंशोग को याद रखेंगे।

इसी तरह फुंशोग भी खुद को आग लगाने की वजह से नहीं मरे हैं, जलने के अलावा उन्हें पीटने से भी काफी चोट आई। उन्हें पीट–पीट कर मार डाला गया। इसलिए तिब्बती जनता के दमन के दिन की याद करने वाले 16 मार्च को लोग हमेशा 20 साल के भिक्षु फुंशोग को याद रखेंगे।

चकित रह गए लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई, पूरी सड़क पर भारी हथियारों से लैस विशेष बल, सैन्य बल, साधारण पुलिस और सादे वर्दी में तैनात पुलिस के जवान भर गए। वे क्रूरता से फुंसोक पर थप्पड़ बरसाने लगे, समझ में नहीं आ रहा था कि वे आग बुझा रहे थे या उन्हें पीट रहे थे!

17 मार्च को सुबह 3 बजे फुंशोग का निधन हो गया। वह 1991 में जन्मे थे यानी सिर्फ 20 साल की उम्र के थे। उनके माता–पिता नाबा काउंटी में स्थित मेउरामा टाउनशिप में स्थित एक गांव से थे। कीर्ति मठ के दो भिक्षुओं की कहानी भी आपको बताते हैं, एक तिब्बत के भीतर ही कहीं रहते हैं और दूसरे पिछले साल बर्फीले पहाड़ों को पार कर अपनी जान बचाते हुए धर्मशाला पहुंच गए। मैंने और मेरे कई दोस्तों ने इन भिक्षुओं का इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने यह देखा कि फुंसोग को सैन्य पुलिस के जवान पीट रहे हैं तो कुछ भिक्षु और अन्य लोग तुरंत उस तरफ भागे। वे लोग उन्हें मंदिर के पास स्थित अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक अस्पताल बंद हो चुका था। इसके बाद वे उन्हें उनके आवास पर ले जाया गया जहां उनके मां–बाप को यह देखकर आंसुओं का सैलाब टूट पड़ा। इसके बाद उन्हें काउंटी अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उन्हें भरती करने से इनकार कर दिया। उनकी जान बचाने के लिए अंत में परिवार ने यह तय किया कि प्रशासन के लोगों से फुंशोग की जान बचाने की भीख मांगी जाए। तब तक शाम के पांच बज चुके थे। देर शाम को आखिर अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने की इजाजत दे दी लेकिन तब तक सारी उम्मीद खत्म हो गई थी और आखिरकार सुबह 3 बजे फुंत्सोग परलोक सिधार गए। सुबह 4 बजे तक अस्पताल प्रशासन उनके शव को परिजनों को सौंपने से इनकार करता रहा। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने फुंशोग को एक भौतिक एवं मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के रूप में प्रचारित करना शुरू किया, उसने मठ और उसके भिक्षुओं को हत्यारों के रूप में देखना शुरू किया। पिछले साल 27 फरवरी को भी शिनहुआ ने ऐसे ही कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, जब कीर्ति मठ के एक भिक्षु तापे ने बीच सड़क पर अपने आपको आग लगा लिया था और इसके बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी। जब इस बारे में विदेशी मीडिया में खूब खबरें आनी शुरू हो गईं तो शिनहुआ ने यह स्वीकार किया कि 'गेरुआ वस्त्र पहने एक आदमी ने खुद को आग लगा लिया है', लेकिन एजेंसी ने कहीं भी यह नहीं लिखा कि सैन्य पुलिस ने उसे गोली मारी है। इसी तरह फुंशोग भी खुद को आग लगाने की वजह से नहीं मरे हैं, जलने के अलावा उन्हें पीटने से भी काफी चोट आई। उन्हें पीट–पीट कर मार डाला गया। इसलिए तिब्बती जनता के दमन के दिन की याद करने वाले 16 मार्च को लोग हमेशा 20 साल के भिक्षु फुंशोग को याद रखेंगे।

शोक एवं संवेदना संदेश

1 यह जानकर अत्यंत पीडा हुई स्वर्गीय श्री पी. के. दिवया जी के अकस्मात दिल का दौरा पढ़ने से निधन 25 अप्रैल, 2011 का समाचार मिला। अपितु तिब्बत मुक्ति सधना में उनका बहुमूल्य योगदान रहा जो किसी से छिपा नहीं। जिससे उन्हें तिब्बती समुदाय हमेषा उनका कृतज्ञता रहेगा।

तिब्बत के स्वराज्य सम्बन्धित गतिविधियों में भी उनका सहयोग अत्यंत प्रषंसनीय एवं अग्रणी रहा है। वे क्रोर ग्रुप दक्षिण क्षेत्र के सह संयोजक एवं भारत तिब्बत मैत्री संघ, मैसूर के अध्यक्ष भी रहे।

हम स्वर्गीय श्री पी. के. दिवया जी के प्रति अपने श्रदासुमन अर्पित करते है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते है कि उनकी आत्मा को असीम शांति तथा उनके परिवारजनों को मानसिक बल प्रदान करें।

2 यह जानकर अत्यंत पीडा हुई स्वर्गीय श्री बैजनाथ प्रसाद जी के अकस्मात हृदय गति के रूकने से निधन 6 अप्रैल, 2011 का समाचार मिला। सम्पूर्ण भारत व अपितु तिब्बत मुक्ति सधना में उनका बहुमूल्य योगदान रहा जो किसी से छिपा नहीं। जिससे उन्हें तिब्बती समुदाय हमेशा उनका कृतज्ञता रहेगा।

तिब्बत के स्वराज्य सम्बन्धित गतिविधियों में भी उनका सहयोग अत्यंत प्रषंसनीय एवं अग्रणी रहा है। वे भारत तिब्बत मैत्री संघ, हजारीबाग के अध्यक्ष भी रहे।

हम स्वर्गीय श्री बैजनाथ प्रसाद जी के प्रति अपने श्रदासुमन अर्पित करते है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते है कि उनकी आत्मा को असीम शांति तथा उनके परिवारजनों को मानसिक बल प्रदान करें ।

भवदीय

भारत तिब्बत समन्वय केंद्र